भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 157

उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2026

सोमवार, 29 आषाढ़, 1948 (शक)

कौशल में कमी दूर करने संबंधी कृतिकबल

†157. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2018 में 'कौशल में कमी दूर करने संबंधी कृतिकबल' का गठन करने के लिए विश्व आर्थिक मंच और इन्फोसिस के साथ साझेदारी की थी;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कृतिकबल द्वारा हासिल किए गए प्रमुख लक्ष्य/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास और साक्षरता नीति, 2015 में एक उद्देश्य के रूप में यह घोषित किया गया था कि वर्ष 2020 तक देश के 25 प्रतिशत स्कूलों में कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्होंने कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत में कौशल अंतराल को कम करने के लिए इंफोसिस और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से अक्तूबर 2018 को एक कार्य बल का गठन किया गया। इस कार्य बल का उद्देश्य भारत में कौशल अंतराल को दूर करने और भारतीय कार्यबल को भावी नौकरियों के लिए तैयार करने हेतु एक कार्य योजना विकसित करना था। इसके गठन के बाद, स्किल्स गैप एक्सेलेरेटर इंडिया ने राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप देने और चार कार्य समूहों के गठन के लिए नेतृत्व समूह की कई बैठकें आयोजित कीं, जिनमें से एक बैठक इंडिया इकोनॉमिक समिट 2019 में हुई थी। एक्सेलेरेटर के सदस्यों को अभिनव सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से चार कार्य समूहों में से एक या उससे अधिक में योगदान देने का अवसर मिला। एक्सेलेरेटर ने राष्ट्रीय कार्य योजना को मंजूरी दे दी; हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण कार्य में और देरी हुई। महामारी के बाद, चर्चाओं में गतिशील नौकरी परिवर्तन, रोजगार सृजन और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले मॉडलों और पहलों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(ग) राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के नीतिगत ढांचे के अनुसार उद्यमशीलता नीति 2015 के अनुसार, आगामी 5 वर्षों में 25 प्रतिशत स्कूल कक्षा 9 से ही कौशलीकरण को औपचारिक शिक्षा में एकीकृत करेंगे, ताकि कौशल विकास को एक प्रेरणादायक विषय बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी सभी शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की है।

(घ) देश में कुल 31,477 स्कूलों को औपचारिक शिक्षा (कक्षा 9-12) के साथ कौशलीकरण को एकीकृत करने के लिए अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 25,181 स्कूलों में इसे लागू किया जा चुका है और इनमें 39,49,875 छात्र नामांकित हैं।

*****